payment of Rs. 10 lakhs towards management fees.

(iii) Loss of potential revenue of Rs. 19.73 crores due to delay in supplies coupled with deficient project management.

(iv) Payment of lease rental of Rs. 7.18 crores in advance before completion of supplies.

(v) Non-utilization of switching capacity to optimum level.

(vi) Irregular payment of Sales Tax and Octroi by certain units.

(c) The irregularities pointed out by the CAG are under examination by the DOT.

पुलिस थानों को जोड़ने के लिए "पोलनेट" परियोजना

*460. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश में सभी जिला पुलिस थानों को पुलिस मुख्यालयों से जोड़ने के लिए उपग्रह दूरसंचार प्रणाली "पोलनेट" का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवें वित्त आयोग ने राज्य को आवश्यक धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए "पोलनेट" परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्ता): (क) से (छ) "पोलनेट" परियोजना का ध्येय, एक उपग्रह आधारित संचार प्रणाली के माध्यम से वर्तमान पुलिस संचार प्रणाली का उन्नयन करना है। इस परियोजना से देश में पुलिस बलों को वॉयस / डाटा / फैक्स और कम्प्यूटर संचार पर अति विश्वसनीय, तीव्र गतिशील और अबाध संचार उपलब्ध होगा।

प्रस्ताव में पुलिस के लिए दूरसंचार विभाग से एक उपग्रह ट्रांसपोन्डर किराए पर लेकर इससे 833 वी-सैट्स को जोड़ने की बात की गई है ताकि जरूरत के आधार पर एक दूसरे के साथ वॉयस / डाटा / फैक्स पर सीधा संचार कायम किया जा सके। मुख्य भूकेन्द्र (मास्टर अर्थ स्टेशन) नई दिल्ली में अवस्थित होगा और वी-सैट टर्मिनल राष्ट्रीय राजधानी, राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के चुनिंदा अवस्थानों पर अवस्थित होंगे। जिला मुख्यालय स्तर से नीचे पुलिस स्टेशन / सीमा चौकियों को, मौजूदा संचार नेटवर्क पर ही इससे जोड़ दिया जाएगा।

परियोजना की सकल अनावर्ती लागत 137.91 करोड़ रु० है। जहां दसवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 21 राज्यों के हिस्से की पूर्ति के लिए 77.51 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराने की सिफारिश की है वहीं आयोग ने गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के अंश के वित्तपोषण की सिफारिश नहीं की क्योंकि ऐसा माना गया कि इन राज्यों के पास अधिशेष राजस्व है। इन चारों राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से परियोजना हेतु धन उपलब्ध कराएं।

अन्तर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति में योजना का अनुमोदन कर दिया है और गैर-योजनागत व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन मांगा गया है।

इस परियोजना को पूरा करने के लिए तीन वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Opening of new Branch Post Offices in Bihar

3339. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of Branch Post Offices sanctioned and opened district-wise during 1995-96 and 1996-97 in Bihar;

(b) the number of Gram Panchayats district-wise in Bihar which do not have Branch Post Offices; and

(c) the steps being taken by Government to provide postal facilities in all Gram Panchayats in the State?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) No Branch Post Office was sanctioned in Bihar during 1995-96. In 1996-97, 24 Branch Post Offices were sanctioned. 23 out of these have been opened. The district-wise details of Extra-Departmental Post Offices sanctioned and opened during 1996-97 are given in the enclosed statement-I (*see* below).

(b) The district-wise number of Gram Panchayats which do not have Extra Departmental Branch Post Offices is given in the enclosed statement-II (*see* below).

(c) Post Offices are opened on norm based justification subject to availability of targets and resources. The policy of Department is to give preference to Gram Panchayat Headquarter villages for the purpose of opening post office. In 1997-98 it is proposed to open 40 Extra-departmental Branch Post Offices in Bihar.

Statement-I

Details of Extra-Departmental Post Offices sanctioned and opened during 1996-97

BIHAR

Sl. No.	Name of District	Name of P.O.	Date of opening
1.	Saran	Saraya Basant	08.01.97
2.	Sheikhpura	Penhasa	27.01.97
3.	Gumla	Khereng	21.12.96
4.	Gumla	Karida	23.12.96
5.	Gumla	Arko	29.03.97
6.	Ranchi	Bokaro	04.12.96
7.	Ranchi	Devgaon	07.12.96
8.	W. Singhbhum	Gulia	17.12.96
9.	W. Singhbhum	Tuta	06.12.96
10.	Siwan	Jalalpur	22.01.97
11.	Rohtas	Majhigaon	24.12.96
12.	Pakur	Mahul Bona	06.12.96
13.	Gaya	Eguna	26.12.96
14.	Begusarai	Nakti Tola (Ramdevi)	13.01.97
15.	Bhojpur	Dillian	21.01.97
16.	Patna	Sahora	17.01.97
17.	Patna	Tartar	27.01.97
18.	Supaul	Mahadeo Asthan	10.01.97
19.	Saharsa	Dharmapur	30.01.97
20.	Sitamarhi	Manariya	27.01.97
21.	Nalanda	Machaldiha	29.03.97
22.	Madhepura	Jiwachpur	31.03.97
23.	Samastipur	Hardaspur Diara	31.03.97
24.	Gaya	Bhaluwa (Sanctioned)	

Statement-II

District-wise number of Gram Panchayats which do not have extra departmental branch post offices in Bihar

S. No.	Name of District	Total number of village panchayat where postal facilities have not been provided
1.	Saran	38
2.	Vaishali	105
3.	Bhojpur	40
4.	Buxar	16
5.	Gaya	129
6.	Nawada	33
7.	Johanabad	42
8.	Nalanda	26
9.	Bhagalpur	56
10.	Banka	46
11.	Patna	103
12.	Begusarai	36
13.	Khagaria	16
14.	Darbhanga	69
15.	East Champaran	130
16.	West Champaran	42
17.	Madhubani	69
18.	Munger	55
19.	Lakhisarai	16
20.	Sheikhpura	17
21.	Jamui	44
22.	Muzaffarpur	53
23.	Araria	49
24.	Katihar	51
25.	Kishanganj	33
26.	Purnea	71
27.	Saharsa	25
28.	Madhepura	25
29.	Suapul	24
30.	Siwan	18
31.	Gopalganj	60
32.	Sitamarhi	40
33.	Sheohar	13
34.	Samastipur	44
35.	Dumka	90
36.	Pakur	25
37.	B. Deoghar	74
38.	Godda	74
39.	Sahebganj	125
40.	Aurangabad	81
41.	Palamu	123
42.	Garhwa	36
43.	Hazaribagh	82
44.	Kodarma	11
45.	Chatra	20
46.	Giridiha	66
47.	W. Singhbhum	147
48.	E. Singhbhum	42
49.	Ranchi	125
50.	Gumla	82
51.	Lohardaga	32
52.	Dhanbad	69
53.	Bodaro	82
54.	Rohtas	107
55.	Babhua	80
	TOTAL:	3207

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में दूरसंचार नेटवर्क का विकास

3340. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अल्मोड़ा जिले के बासोट, तया, सीम और कोटा गिवाई डाक-घरों में टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ख) इसके क्या कारण है और इन डाक-घरों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) अल्मोड़ा जिले में टेलीफोन नेटवर्क के विकास हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) बासोट में, एक टेलीफोन नं॰ 8427 भीकिया सेन एक्सचेंज से पहले से ही कार्यरत है।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान तया, सीमा, कोटागिवई ग्रामों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) प्रदान करने की योजना बनाई गई है।